(v) parliamentary approval for all future Public Private Projects (PPP) or private involvement in key sectors such as defence, airports, ports and national highways; and

(vi) bring Public Private Projects (PPP) and projects involving rare natural resources, sovereign functions and services, etc. under the purview of Lokpal."

MR. DEPUTY CHAIRMAN: The Resolution moved by Mr. Balagopal will be taken up on the next day in the next session when the Private Members/Business (Resolutions) is slated.

SHRI D. RAJA (Tamil Nadu): It can be taken up on the next day of the next session when the Private Members' Business is taken up.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: That is what I am saying. Now, Mr. Piyush Goyal. You have 12 minutes exactly. After 12 minutes you should stop.

THE INTERIM BUDGET (GENERAL) 2014-15
AND
GOVERNMENT BILLS — *Contd.*

(i) The Appropriation (Vote on Account) Bill, 2014
(ii) The Appropriation Bill, 2014
and
(iii) The Finance Bill, 2014

श्री पीयूष गोयल : उपसभापति महोदय, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। आज दस वर्ष के बाद इस सरकार ने अपने ट्रू कलर्स जनता को दिखा दिए हैं। एक तरफ तो यह सरकार फिस्कल कंसॉलिडेशन और देश के आर्थिक सुधार की बात करती है, लेकिन दूसरी तरफ हज़ारों करोड़ रुपए "भारत निर्माण" के एड्वर्टिज़मेंट्स पर खर्च करके, जहां भारत परेशान है, पूरी जनता इस सरकार के कारनामों से दुःखी है, उस परेशान जनता के घावों पर यह सरकार नमक छिड़कती है। दूसरी तरफ जो आधारभूत सुविधाएं हैं, जो काम देश की सुरक्षा से जुड़े हुए हैं, होम मिनिस्ट्री हो, माइनॉरिटी डेवलपमेंट मिनिस्ट्री हो, स्किल डेवलपमेंट हो, उन सबके कामों में यह सरकार पैसा भी नहीं देती है। मनरेगा की स्कीम में भी पैसा नहीं देती है और आखिर में हम देखते हैं कि एक सरकार जिसने पूरी जनता के साथ * किया, सालों-साल उनको गलत चीज़ें बताकर इस उम्मीद में रखा कि अब उनका समय सुधरेगा, लेकिन वस्तुस्थिति यह है कि समाज का कोई वर्ग ऐसा नहीं है, जो इस सरकार से खुश हो। इन्होंने सिग्युलर्ली ऐसी सिचुएशन क्रिएट की कि हर वर्ग को दुःखी किया, चाहे वह नौजवान हो या युवती हो, जो चाहती हो कि अच्छी तालीम मिले, क्वालिटी ऑफ एजुकेशन अच्छी हो। ये कहते हैं कि हम स्कूलों में यह कर देंगे, हम पैसा खर्च करेंगे, लेकिन क्वालिटी मत मांगो, अच्छी तालीम हम नहीं दे सकते। दुनिया हमारे ऊपर हंसती है कि यह सरकार एक अच्छी तालीम

---

*Expunged as ordered by the Chair.

[श्री पीयूष गोयल]

नहीं दे सकती, अच्छी नौकरी करने के लिए, अच्छा काम करने के लिए युवा को तैयार नहीं कर सकती।

महोदय, महिलाओं और गृहिणियों की हालत तो सारी दुनिया देख रही है। महंगाई आसमान छू रही है, चाहे वे प्याज़ के दाम हों, चाहे टमाटर, आलू, गेहूं, दूध, दही, घी, कुछ भी हो। मैं नॉन-वेज नहीं खाता लेकिन मुझे विश्वास है कि चिकन-मटन के दाम भी इस देश में कुछ बचे नहीं होंगे। यहां तक कि चाय के दाम भी इन्होंने बढ़ा दिए। चाय, जो एक सामान्य आदमी पीता है और सामान्य आदमी बेचता है, उस चाय के दाम को भी इस सरकार ने नहीं छोड़ा, लेकिन अब जनता को यह भरोसा है कि जिस सरकार के नेतृत्व में इतनी मुसीबत लोगों ने झेली है, उसके उपाय वाला भी अब चाय वाला ही बनेगा। अब हम उम्मीद करते हैं कि जल्दी से जल्दी इस * को जनता उसके घर बैठाए और एक चाय वाले को एक उपाय वाले के रूप में लाकर इस देश की समस्याओं का निराकरण करे।

सर, किसानों की समस्याएं देखिए। आप देखिए कि इस सरकार ने फर्टिलाइज़र प्राइसेज तीन सौ, चार सौ प्रतिशत बढ़ा दिए हैं। यह सरकार कहती है कि मिनिमम सपोर्ट प्राइस बढ़ाएंगे, लेकिन जब महंगाई इतनी ज्यादा हो, इन्फ्लेशन इतना बढ़ रहा हो, उस दौरान अगर ये थोड़ा मिनिमम सपोर्ट प्राइस बढ़ाते हैं, तो उससे फार्मर को, किसान को कोई लाभ नहीं है। किसान फिर भी महंगाई के बोझ के तले दबा हुआ है। सर, पानी की समस्या है, बिजली की समस्या है। किसानों के साथ ऐसी परिस्थिति है कि तीन साल उत्पादन बढ़ा नहीं और चौथे साल में थोड़ा बढ़ा, तो ये ऐसे कहते हैं, जैसे हमने बहुत बड़ा काम कर लिया हो। वस्तुस्थिति यह है कि आज भी हज़ारों किसान हर वर्ष आत्महत्या करते हैं, अपनी जान की बाज़ी देते हैं, कर्ज़ में डूबे हुए हैं, बैंकों से परेशान हैं, मनीलेंडर्स से परेशान हैं और इस सरकार से परेशान हैं। ऐसी परिस्थिति में इस देश के किसान दु:खी हैं। निवेशक, चाहे वे विदेशी हों या भारतीय हों, वे भी दु:खी हैं। इन्होंने पूरा इन्वेस्ट्मेंट साइकिल ब्लॉक कर दिया, बंद कर दिया। पिछले तीन वर्ष से भारत में नए प्रोजेक्ट नहीं आ रहे थे। इनकी सरकार के आपसी झगड़ों के कारण कोई प्रोजेक्ट क्लीयर नहीं हो रहा था। एन्वायर्नमेंट मिनिस्ट्री पहले प्रोजेक्ट्स को बंद करके बैठी थी। एक मंत्री हटा, दूसरा आया। दूसरे मंत्री ने फिर प्रोजेक्ट्स को क्लीयर करने के लिए अनाप-शनाप कंडीशन्स डाल दीं। इस सरकार ने ऐसी परिस्थिति पैदा कर दी कि तीन वर्ष के आखिर में भी आज की परिस्थिति यह है कि ये कहते हैं कि कैबिनेट कमेटी ने प्रोजेक्ट्स क्लीयर किए हैं, लेकिन वस्तुस्थिति यह है कि वे सब प्रोजेक्ट्स अटके हुए हैं, बैंक उन्हें पैसा नहीं दे रहे हैं, उनके पास लगाने के लिए पैसा नहीं है। आज सभी प्रोजेक्ट्स देश भर में ठप हैं। लोगों को इस सरकार पर विश्वास नहीं है और विश्वास न होने के कारण इस सरकार के रहते इस देश का इन्वेस्ट्मेंट साइकिल भी नहीं सुधरेगा। आज परिस्थिति ऐसी है कि इनके इन्कम टैक्स ऑफिसर्स, इनके सरकारी अफसर लोगों को इतना ज्यादा हरैस कर रहे हैं कि कोई विदेशी कंपनी भी यहां नहीं बची, जो बिना इनके हरैसमेंट के रहती, चाहे वह इन्कम टैक्स हो, सर्विस टैक्स हो, कस्टम हो या एक्साइज़ हो। हरेक के इतने क्लेम्स

*Expunged as ordered by the Chair.

डाल रखे हैं, ट्रांसफर प्राइसिंग के ऊपर इतने ज्यादा कन्फ्यूज़ंस इस सरकार ने क्रिएट कर रखे हैं कि जो कम्पनियां यहां हैं और जो कम्पनियां यह समझती थीं कि हम यहां पर अपना कारोबार और बढ़ाएंगे, उन्होंने भी आजकल अपना कारोबार बढ़ाना बंद कर दिया है। किसी कम्पनी पर 11,000 करोड़ का क्लेम, किसी कम्पनी पर 5,000 करोड़ का क्लेम! हमें समझ में नहीं आता कि यह सरकार एक तरफ तो यह कहती है कि एफडीआई लाएंगे, एक तरफ तो कहती है कि देश में निवेश आए, करंट अकाउंट डेफेसिट कंट्रोल हो और दूसरी तरफ इतनी परेशानियों का माहौल है कि न स्मॉल स्केल इंडस्ट्री, न ही मैनुफैक्चरर — कोई उत्पादक आज इस देश में खुश नहीं है। आयात-निर्यात की भी स्थिति ऐसी है कि एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट दोनों गिर रहे हैं। Growth of exports has fallen badly to about five or six per cent and imports are down. इम्पोर्ट्स के डाउन होने में एक बहुत बड़ा खतरा है। वास्तव में कैपिटल गुड्स इम्पोर्ट गिरा है और जब कैपिटल गुड्स नहीं आएंगे तो नयी मैनुफैक्चरिंग, नयी सप्लाई इस देश में नहीं आएगी। ऐसी परिस्थिति में जो महंगाई है, जिसका अगर कोई सॉल्युशन है तो वह सप्लाई साइड में है, उस सॉल्युशन से भी यह सरकार जनता को वंचित रखेगी और महंगाई को नहीं रोक पाएगी। इन्फ्रास्ट्रक्चर की व्यवस्था तो आप लोग देख ही रहे हैं। आधारभूत सुविधाएं — चाहे वह बिजली हो, पानी हो, सड़कें हों, रेलवे हो, एयरपोर्ट्स हों या माइनिंग हो — हरेक जगह पर उत्पादन गिरता जा रहा है। ये लोग स्टेटस्टिक्स के छल में बोलते रहेंगे, ऐवरेज ग्रोथ बढ़ी है, ऐवरेज रेट बढ़ा है, लेकिन अगर आप रीयल एक्सचेंज रेट देखें, रीयल इफेक्टिव ऐक्सचेंज रेट के साथ ग्रोथ की तुलना करें तो वस्तुस्थिति यह है कि इन्होंने देश की पूरी अर्थव्यवस्था को बिगाड़ दिया है, अर्थव्यवस्था को ऐसी मोड़ पर लाकर खड़ा किया है कि जो परिस्थिति, जो व्यवस्था 1991 में थी, लगभग उसी प्रकार की व्यवस्था आज देश में ये लोग छोड़कर जा रहे हैं। अगर आज आप पेपर में पढ़ें तो इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड, जिसका ये कई बार नाम लेते हैं कि इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड इस सरकार के फिस्कल कंसोलिडेशन की बहुत तारीफ कर रहा है, उसने भी यही कहा है। मैं आज के बिज़िनेस स्टैंडर्ड से कोट करता हूं: "About two-thirds of the slowdown in India can be explained by domestic forces." ये पूरे टाइम ग्लोबल फोर्सेज़, अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था का बयान देते हैं। वास्तव में आईएमएफ खुद कहता है कि डोमेस्टिक कारणों से हम आज इतना सफर कर रहे हैं। Further, it says, "Besides policy uncertainly, the domestic causes of the slowdown include supply bottlenecks, delayed project approvals and implementation." चाहे इनके वित्त मंत्री कितनी भी अपनी पीठ थपथपा लें कि हमने बहुत अच्छा काम किया है, दुनिया ने देख लिया है कि इस सरकार ने कैसे भारत की अर्थव्यवस्था को बिगाड़ा। इस भारत की अर्थव्यवस्था को, जिसको भारतीय जनता पार्टी ने, एनडीए ने 2004 में एकदम मज़बूत स्थिति में इनके हाथ में सौंपा था, उसको किस प्रकार से इन्होंने ऐसे ज़मीन पर लाकर खड़ा कर दिया कि भारत की ग्रोथ भी चार प्रतिशत, डबल डिजिट इन्फ्लेशन, 6 वर्ष से दस प्रतिशत से ज्यादा महंगाई और वास्तव में जो खाद्य उत्पाद हैं, जो खान-पान की वस्तुएं हैं, फूड आर्टिकल्स में लगभग 20 प्रतिशत महंगाई इनके कार्यकाल में रही है, खासकर यूपीए-2 के कार्यकाल में। उसका भुगतान जनता इनको आने वाले चुनाव में अच्छा सबक देकर करेगी। इनके खुद के सरकारी आंकड़े देखिए। ये कहते हैं कि इन्होंने फिस्कल कंसोलिडेशन किया। फिस्कल कंसोलिडेशन कैसे किया? तीन रास्तों से किया। पहली बात तो इन्होंने कैपिटल एक्सपेंडिचर बंद कर दिया। सरकार का एक काम होता है कि जब बजट पर खर्चा करे, प्लान एक्सपेंडिचर करे, उससे

[श्री पीयूष गोयल]

कुछ सुविधाएं, उससे कुछ अच्छे कैपिटल ऐसेट्स क्रिएट हों। इस सरकार ने कैपिटल ऐसेट्स को रोका है। आज परिस्थिति ऐसी है कि बजट आउटले के खर्चे में से जहां एक ज़माने में 22-23 प्रतिशत खर्चा कैपिटल ऐक्सपेंडिचर पर होता था, आज वह 11-12 प्रतिशत पर लाकर रख दिया है। आज यह परिस्थिति है कि सरकार ऋण लेती है, डैट खड़ा करती है, अपने बजट को भरने के लिए लोन लेती है, लेकिन उस लोन को लेने के बाद कुछ सुविधाएं नहीं देती बल्कि उसको अपनी तनख्वाहों और पीएसयू के लॉसेज़ को भरने में लगा देती है। Wasteful expenditure is the only expenditure which the Government has been doing. दूसरा, इन्होंने अभी तक पूरे खर्चे प्रोवाइड नहीं किए हैं। जो असली खर्चा सब्सिडी का है, वह अभी तक हमें मालूम नहीं है। रिपोर्ट्स कहती हैं कि अभी तक इन्होंने सवा लाख करोड़ के खर्चे बजट में नहीं दिखाए हैं। इस प्रकार से वास्तव में जो बजट है, उसमें 4.6 नहीं, 6 प्रतिशत तक फिस्कल डेफेसिट आने का अनुमान है। फिर ये कहते हैं कि हमने बजट पर बहुत सारे promises दिए थे। सबसे बड़ी बात श्री एन.के. सिंह, बिहार के सांसद कहते हैं कि इन्होंने वायदा दिया था और उस वायदे के ऊपर एक तरीके से कई लोगों को छल में रखा कि हम बैकवर्ड रीजन्स के लिए साढ़े ग्यारह हजार करोड़ देंगे। पिछले बजट में promise किया गया बैकवर्ड रीजन्स ग्रांट फंड के लिए साढ़े ग्यारह हजार करोड़ रुपये देने का, अब कहते हैं कि कमेटी बैठी है। सरकार ने साढे ग्यारह हजार करोड़ रुपये वापस ले लिए और कमेटी का कोई निर्णय नही है। अब तो समय यह आ गया है कि जो भारत का पूर्वी इलाका है जो आज विकास के कार्य से वंचित है, प्रोग्रेस से, डेवलेपमेंट से वंचित हैं। नौकरियां नहीं हैं, लोग दु:खी हैं। ...**(समय की घंटी)**... उस इलाके का अगर कोई विकास कर सकता है, कोई अच्छा काम कर सकता है, उसका उद्धार कर सकता है, तो वह है नरेन्द्र मोदी। जिन्होंने साबित कर दिखाया है कि पश्चिम में किस प्रकार की प्रगति हुई है कि पूर्व में आपने किस प्रकार से लोगों को दु:खी रखा है। उन्होंने कहा है कि पूरे देश में समान न्याय होना चाहिए।...**(व्यवधान)**... हर वर्ग को, हर रीजन को, हर व्यक्ति को, चाहे वह पूर्व से हो, चाहे पश्चिम से हो, चाहे दक्षिण से हो, पूरे भारत का अगर कोई सुधार कर सकता है...**(व्यवधान)**... इन बैकवर्ड रीजन्स में इन्होंने कोई काम नहीं किया है, वह काम भी मुझे लगता है कि नई सरकार आकर करेगी और श्री नरेन्द्र मोदी ही कर सकते हैं। इस सरकार के बजट से हम दु:खी हैं। इस वोट एंड अकाउंट में कई चीजें अभी आई नहीं हैं। हम चाहते हैं कि एक सच्चे भारत की अर्थ-व्यवस्था का ब्यौरा ये दें, ऐसी हमारी इनसे उम्मीद है। धन्यवाद।

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Thank you for sticking to time. You have used two words which are unparliamentary, * और "छल" They are unparliamentary. ...*(Interruptions)*...

श्री रवि शंकर प्रसाद (बिहार) : सर, मैं आपसे यह जानना चाहूंगा कि "छल" कैसे unparliamentary हो गया? जिसने भी यह किताब बनाई है, छल, प्रपंच तो हिन्दी साहित्य का एक अंग है, उस पर यह व्यंग्य होता है। अब आप छल को संसद में नहीं कहने देंगे, तो यह तो हिन्दी साहित्य का अपमान है।...**(व्यवधान)**... माननीय उपसभापति जी, मैं चाहूंगा कि सतीश मिश्रा जी इस पर कुछ

*Expunged as ordered by the Chair.

प्रकाश डालें।...**(व्यवधान)**... आप भी इस पर कुछ बोलिए, यह बहुत गंभीर विषय है।...**(व्यवधान)**... यह जिसने भी बनाया है, यह हिन्दी साहित्य का अपमान है।...**(व्यवधान)**...

श्री उपसभापति : आप सुनिए।...**(व्यवधान)**...

श्री रवि शंकर प्रसाद : हम लोग तो हिन्दी प्रांत के लोग हैं और हिन्दी साहित्य का...**(व्यवधान)**...

MR. DEPUTY CHAIRMAN: I will reply to you. मैं तो हिन्दी बिल्कुल नही जानता, लेकिन इस किताब में ...**(व्यवधान)**...

श्री रवि शंकर प्रसाद : चतुर्वेदी जी, आप ही इस पर कुछ प्रकाश डालिए कि छल, प्रपंच...**(व्यवधान)**...

श्री उपसभापति : श्री रवि शंकर प्रसाद जी,...**(व्यवधान)**...

श्री सत्यव्रत चतुर्वेदी (मध्य प्रदेश) : इनके ये पसंदीदा शब्द हैं।...**(व्यवधान)**... छल और प्रपंच...**(व्यवधान)**... लोक सभा ने जो unparliamentary words की सूची की एक किताब निकाली है, उसमें...**(व्यवधान)**...

श्री रवि शंकर प्रसाद : नहीं, नहीं। मैं हिन्दी साहित्य की बात कर रहा हूं।...**(व्यवधान)**...

श्री सत्यव्रत चतुर्वेदी : ये आपके पसंदीदा शब्द हैं तो...**(व्यवधान)**...

MR. DEPUTY CHAIRMAN: I don't dispute about it. I am not a scholar of Hindi. लेकिन इतना है, I can re-consider what I said. ...*(Interruptions)*... सुनिए। For you information, Lok Sabha Secretariat's book on "Unparliamentary Expressions" says. ...*(Interruptions)*... Chhal-kapat ...*(Interruptions)*...

श्री रवि शंकर प्रसाद : चतुर्वेदी जी, बहुत विद्वान व्यक्ति हैं।...**(व्यवधान)**...

श्री सत्यव्रत चतुर्वेदी : Unparliamentary Words की एक सूची है उसमें अकेले ये शब्द ही नही डाले हैं।...**(व्यवधान)**...

MR. DEPUTY CHAIRMAN: I will re-consider it. ...*(Interruptions)*... Now, Shri Rama Chandra Khuntia.

श्री सतीश चन्द्र मिश्रा (उत्तर प्रदेश): सर, छल और कपट शब्द हट जायेंगे, तो भारतीय जनता पार्टी के पास बचेगा क्या?...**(व्यवधान)**...

SHRI RAMA CHANDRA KHUNTIA (Odisha): Hon. Deputy Chairman, Sir, I must congratulate the hon. Prime Minister, hon. Finance Minister and the UPA Government for presenting this Budget. Sir, in spite of global economy in mess and the developed countries of the Europe, the USA, Japan, including China, whose growth rate has been drastically reduced to a single digit — it was 13 per cent at one point of time — which is just 2 per cent more than India and in some countries the growth rate is -1 per cent, the hon. Finance Minister, with inputs from the hon. Prime Minister, presented very good Budget and has been able to manage the economic situation of

[Shri Rama Chandra Khuntia]

the country well. He has presented a Budget in this difficult situation without imposing any tax on the common man and has been able to reduce tax on various essential items being used by general public in this country. Sir, now, we are talking about agriculture.

SHRI TAPAN KUMAR SEN (West Bengal): I am not questioning that. ...*(Interruptions)*... I want to know whether they have fallen from the grace of the IMF ...*(Interruptions)*...

SHRI RAMA CHANDRA KHUNTIA: Tapanji, I am with you. But, should we go back to a situation where the so-called disinvestment was rampant? We are all concerned about disinvestment. I ask a question. I am with you on so many points. But, the point is that this UPA Government has abolished the Disinvestment Department. Who created the Disinvestment Department in this country? Who created the Disinvestment Commission in this country? The Disinvestment Commission in the country was created when leftist people supporting the Government. ...*(Interruptions)*... You should not forget that. ...*(Interruptions)*... Yes; I know. You people were also a party to that. When was the Disinvestment Commission created? ...*(Interruptions)*...

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Mr. Raja, please...*(Interruptions)*...

SHRI RAMA CHANDRA KHUNTIA: I am not talking to you. You know it...*(Interruptions)*... So, don't try to open my mouth. We know when the Disinvestment Commission was created. It is recorded as history in the Government as to when it was created. We know when the Disinvestment Department was crated and we also know when the Disinvestment Department was abolished. So, the question is: With new economic policy and opening up of the market, we must thank this Government which has been able to manage and control the economy, which has been able to protect the interests of the workers without liberalising the labour laws. So, we must appreciate that.

Sir, we are talking about agriculture and agriculture workers. In this country, the agriculture credit limit has been increased to Rs. 7,50,000 crores. It is a great thing to set this as target by this Government. Look at the other thing. Sir, Rs. 75,000 crores worth of agriculture loan was waived; rebate given to various sectors, Rs. 29,000 crores has been given for infrastructure development of railways from Rs. 25,000 crores. Sir, more money has been given to social, education and health sectors. There is an increase of 10 per cent to Defence budget.

If you look at the Budget, the hon. Finance Minister has announced One-Rank-One-Pension. Everybody is saying that this is a good thing. But, I am surprised that no earlier Governments could do this. If those Governments were more concerned about One-Rank-One-Pension, whey did they not do it? This has been done by the UPA Government which is a commendable job. It was the main demand of the Defence personnel.

Sir, I also compliment the hon. Finance Minister for reducing tax on mobiles, cycles, motorcycles, cars, etc. Sir, people are saying that motorcycle, cars, small cars is not luxury. It is a requirement for general workers also who are using the same.

Keeping revenue deficit at 4.6 per cent is a good thing and we have set a target to keep it within 4.1 per cent. Sir, about Rs. 3.6 lakh crores has to be given to the States.

Everybody here was talking about the federal structure. Sir, the States are giving more money, disbursing more money, and I feel the UPA Government has done a very good thing in empowering the States and giving them more and more money. Many States had been demanding more money earlier. Look at the Food Security Bill, the Government has given more money. Then, they have given Rs. 1,000 crores as Nirbhaya Fund, and this is Non-Lapsable. This has been given for the protection of women. The Government has given a special fund for preserving the greenery in the eastern parts of India. I am also proud of the fact that this year Odisha has been given a prize for increasing its agricultural production. Sir, this could happen because the then Finance Minister had given a package to the eastern States of India, namely, West Bengal, Assam and Odisha, for increasing their agricultural production. That has yielded results, and I think this is a very good thing. The agricultural produce has increased. Emphasis has been laid on the manufacturing sector and exports, which is the need of the hour. Sir, the Government has brought in very progressive legislations like the Food Security Bill, the Right to Education, MNREGA and other laws. This Government has tried to give more and more funds for the social sector, which is a very good thing. Sir, many times we have discussed it; there is corruption; the money which is given by the Government does not reach the people. So, we have to bring in an effective delivery system, expeditiously. This is very much required. We are very thankful to this Government, to the UPA chairperson, Shrimati Sonia Gandhiji, the Prime Minister and also the Finance Minister, for having brought the Lokpal Bill. We fee! That laws like the Citizens' Charter, the Whistle Blowers Protection Bill, etc., are very relevant to the success of the Lokpal and to put a check on corruption. Some of my friends said that we do not want to fulfill the wishes of Rahulji. Sir, is it

[Shri Rama Chandra Khuntia]

wrong? Do they mean to say that because it is Rahulji thinking about something, we will not pass it in the Parliament? I think this is a matter of great concern. ...*(Interruptions)*... Does it mean if Rahulji suggests something, that should not be passed in the Parliament?...*(Interruptions)*...

DR. V. MAITREYAN: Rahulji did not think about it five years ago. He is thinking about it just three months before the elections! ...*(Interruptions)*...

SHRI RAMA CHANDRA KHUNTIA: Sir, what is this? Just because Rahulji was interested in getting the Lokpal Bill passed... ...*(Interruptions)*...

DR. V. MAITREYAN: You did not think about it for four-and-a-half years that you have been in power. ...*(Interruptions)*... He has been a Member for ten years now. ...*(Interruptions)*...

MR. DEPUTY CHAIRMAN: No, please. ...*(Interruptions)*... No, please. ...*(Interruptions)*...

DR. NAJMA A. HEPTULLA: I have a point of order, Sir. ...*(Interruptions)*...

MR. DEPUTY CHAIRMAN: One second. Najmaji has a point of order.

DR. NAJMA A. HEPTULLA: Sir, yesterday, you gave a ruling from the Chair that we should not mention the name of a Member of the other House. Similarly, we have a convention also in this House that names of Members of the other House are not taken here. So, both the names should be expunged.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: You should not criticize them.

SHRI RAMA CHANDRA KHUNTIA: No, I am not criticizing. Sir, I have the right to take the name of the leader of my Party.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Yesterday, I expunged the names. ...*(Interruptions)*...

DR. NAJMA A. HEPTULLA: Mr. Rahul Gandhi is a Member of the other House. So, his name should not be taken here.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Please. ...*(Interruptions)*... Why don't you allow me? ...*(Interruptions)*...

श्री सत्यव्रत चतुर्वेदी : नजमा जी...**(व्यवधान)**... मैं नजमा जी को याद दिलाने जा रहा हूं कि...**(व्यवधान)**... अभी थोड़ी देर पहले पीयूष गोयल जी बोल रहे थे...**(व्यवधान)**... जब वे नरेंद्र मोदी जी का नाम ले रहे थे, तब आपको याद नहीं आया?

3.00 P.M.

डा. वी. मैत्रेयन : आप नाम लीजिए...**(व्यवधान)**... मगर आपको साढ़े चार साल पहले याद क्यों नही आया?...**(व्यवधान)**... आपको अभी याद आया है।...**(व्यवधान)**...

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Let me tell you. ...*(Interruptions)*...

श्री सत्यव्रत चतुर्वेदी : नरेंद्र मोदी जी का नाम लिया जा सकता है...**(व्यवधान)**... राहुल जी का नहीं?...**(व्यवधान)**...

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Okay. Now, allow me to... ...*(Interruptions)*... Let me make it very clear...

SHRI RAMA CHANDRA KHUNTIA: Sir, he can take the name of his leader, but...

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Khuntiaji, please. Let me make it very clear. Yesterday, I expunged one name and the remark about that person because it was an adverse remark about a person who cannot come here and defend himself. But when Mr. Narendra Modi's name is mentioned, or Shri Rahul Gandhi's name is mentioned, these are not adverse remarks. So, both will remain there.

DR. V. MAITREYAN: No. I am only countering what he is saying.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: All right. If it is an adverse remark, I will expunge it. ...*(Interruptions)*... No, no. Any adverse remark will be expunged. ...*(Interruptions)*...

Any adverse remark ...*(Interruptions)*... The rule is very clear that any criticism against any person who cannot come and defend here will be expunged. ...*(Interruptions)*...

DR. V. MAITREYAN: But they cannot take that name like that. ...*(Interruptions)*... I cannot say Rahul Gandhi is a great person. ...*(Interruptions)*...

MR. DEPUTY CHAIRMAN: You can say without mentioning the name. If you criticize, I will expunge it. ...*(Interruptions)*...

डा. नजमा ए. हेपतुल्ला : नाम आप ले रहे हैं, मैं थोड़े ही ले रही हूं। आप नाम क्यों ले रहे हैं?...**(व्यवधान)**...

DR. V. MAITREYAN: He did not think for this Bill in the last four and-a-half years. ...*(Interruptions)*...

SHRI RAMA CHANDRA KHUNTIA: Sir, I don't know why they are so much afraid of Rahulji. ...*(Interruptions)*... Sir, Maitreyanji can take the name of Ms. Jayalalithaa; Najmaji can take the name of Mr. Modi, but, Sir, I have no right to take the name of Shri Rahul Gandhi. ...*(Interruptions)*...

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Mr. Narendra Modi is also remaining there. ...*(Interruptions)*...

DR. V. MAITREYAN: That is for them, Sir. I don't bother.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Any criticism against a person who cannot come and defend here will be expunged. ...*(Interruptions)*...

DR. NAJMA A. HEPTULLA: Sir, it is not adverse. The thing is, Members who are not of this House but Members of the other House, we should not take their names. This the convention. I am only talking about the convention.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: That is the point. I agree with that. ...*(Interruptions)*...

SHRI SATYAVRAT CHATURVEDI: Does it apply to Narendra Modi also? ...*(Interruptions)*... Do you want Narendra Modi's name to be expunged? ...*(Interruptions)*...

MR. DEPUTY CHAIRMAN: That is the convention. There is a point in that. ...*(Interruptions)*... Mr. Khuntia, please. ...*(Interruptions)*...

SHRI SATYAVRAT CHATURVEDI: Are you in favour of Narendra Modi's name to be expunged? ...*(Interruptions)*...

SHRI D. RAJA (Tamil Nadu): Sir,...*(Interruptions)*...

MR. DEPUTY CHAIRMAN: I always allow Raja, who cannot come and defend here. ...*(Interruptions)*... Rajas cannot come, yet we allow it. Then, why do you fight? ...*(Interruptions)*...

श्री सत्यव्रत चतुर्वेदी : अगर आपकी आपत्ति राहुल जी के नाम पर है, तो क्या आपकी आपत्ति नरेन्द्र मोदी के नाम पर भी है?

श्री उपसभापति : चतुर्वेदी जी, आप बैठिए।...**(व्यवधान)**...

श्री सत्यव्रत चतुर्वेदी : और अगर है, तो...**(व्यवधान)**...

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Mr. Khuntia, you speak. They are encroaching on your time. So, you speak. ...*(Interruptions)*...

श्री रवि शंकर प्रसाद : सर, खूंटिआ जी राहुल जी का नाम लें, अभिनंदन करें, शुभकामनाएं दें, कोई बात नहीं है। आप करिए, बढ़िया है।

श्री रामचन्द्र खूंटिआ : धन्यवाद। Sir, what I was saying was this. Yesterday, all the Members of the House had expressed their positive attitude for passing the Bill. What I am saying is this. If any Bill is good — whether it is said or proposed or placed

by Shri Rahul Gandhi or anybody else, how does it matter — it should be supported. So, my intention was, if it is a good Bill, then, it should be passed. If it is a good Bill like the Citizens' Charter, Whistleblower, Judicial Accountability, etc., it should not be opposed just because Shri Rahul Gandhi is insisting on it. ...*(Interruptions)*...

DR. V. MAITREYAN: He did not remember it for nine years. He forgot it for nine years.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Mr. Khuntia, you speak on the Bill.

SHRI RAMA CHANDRA KHUNTIA: That is what I said. It is Shri Rahul Gandhi at whose instance, on whose demand the National Employment Guarantee Programme was extended to the whole of the country. It was on the demand of Shri Rahul Gandhi that One-Rank-One-Pension Scheme was also accepted by the Government.

श्री तपन कुमार सेन : तब आप लेफ्ट के ऊपर डिपेंडेंट थे, इसलिए आपको लाना पड़ा, नहीं तो कोई नहीं लाता।...**(व्यवधान)**... आपका प्लानिंग कमीशन, आपके फाइनांस मिनिस्टर...**(व्यवधान)**... जोक करते थे।...**(व्यवधान)**... आपने 2009 में वोट लिया।...**(व्यवधान)**...

SHRI RAMA CHANDRA KHUNTIA: We appreciate Left's work. We are not opposing the Left. ...*(Interruptions)*... Sir, once upon a time, the Left was with Shri Atal Bihari Vajpayee. When the Left was with the NDA, then, why did they not do it? If the Left was so powerful, when they were with Shri Morarji Desai, when they were with the NDA, why did they not do it then? The thing is this. Because the UPA wanted it — I do appreciate that the Left Parties cooperated in that — and it was done. The question is, if the major party in the Government would not like to legislate a law, even though the supporting parties want it, then, the law cannot be made. The supporting parties cannot do it without the major party. ...*(Interruptions)*... It could happen because the UPA Government wanted to do it. It could not happen at the time of the NDA because the NDA did not want that, even though the Left Parties were supporting it. So, that could not happen.

DR. V. MAITREYAN: Please use Rahul Gandhi's good-offices to pass the Women's Reservation Bill in the other House. ...*(Interruptions)*...

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Mr. Khuntia, don't react to them. You address the Chair. You say what you have to say. Don't react to them. ...*(Interruptions)*... They are only provoking you. You understand that they are provoking you.

SHRI RAMA CHANDRA KHUNTIA: Sir, having said that, I am of the opinion that the Government is even today interested to pass the Whistleblower Bill, to pass

[Shri Rama Chandra Khuntia]

the Citizens' Charter, to pass the Judicial Accountability Bill and other Bills which are good for the people of this country. Before completing my speech, I would like to give a few suggestions to the Government. While appreciating the works of the Government, I suggest that the old-age pension should be enhanced because it is very less.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Please conclude in two minutes.

SHRI RAMA CHANDRA KHUNTIA: Okay, Sir. I would suggest that it should be enhanced to Rs. 1,000/-. This Government also enhanced the Provident Fund related pension to Rs. 1,000/-. I welcome this decision of the Government and thank for that.

I also demand that the general pension should also be minimum Rs. 1,000/-. Similarly, pension schemes, at par with the nationalized banks, should also be there for the officers and employees of the Grameen Banks.

Dearness Allowance of all the Central Government and public sector employees and officers should be merged with the basic pay.

Then, Sir, there are various types of Dearness Allowances. There is the Central Government D.A. There is the Industrial D.A. ...*(Interruptions)*...

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Conclude please.

SHRI RAMA CHANDRA KHUNTIA: Sir, please give me one more minute. There is also a type of DA for the minimum wages workers. So, there are various types of DAs. Since the inflation and the rates of consumable goods are increasing equally for everybody, there should be only one type of DA across all the categories, irrespective of the fact where and how one is working. Weekly working days, working time, gazetted holidays and national holidays should also be equal for everybody. There should also be social security scheme and health care schemes for all the workers.

I think, all these things should be considered by the Government. I wish if there were social security and medical care for all. It would definitely be good for the country.

With these words, I, once again, support this Budget and also the Appropriation Bill.

श्री नरेन्द्र कुमार कश्यप (उत्तर प्रदेश) : उपसभापति जी, मैं आपका धन्यवाद करता हूं कि आपने मुझे विनियोग (लेखानुदान) विधेयक, 2014 पर बोलने का मौका दिया।

महोदय, अभी सत्ता पक्ष की तरफ से बहुत सारी उपलब्धियों और सरकार के कामों का जिक्र किया गया, लेकिन मैं उस तरफ नहीं जाना चाहता। इस विनियोग (लेखानुदान) विधेयक के माध्यम से मैं आपको बताना चाहता हूं कि आज भी कुछ ऐसे मुद्दे हैं, जो अभी तक अनसुलझी पहेली की तरह, खास तौर पर देश के गरीबों के दिलों में दर्द पैदा करते हैं। अगर उनकी ओर सरकार का ध्यान आज भी आकर्षित हो जाए तो शायद एक बड़े सवाल का जवाब सदन को और देश को मिल जाएगा।

महोदय, महंगाई आज भी देश की एक बहुत बड़ी समस्या है। इस महंगाई का सबसे ज्यादा कुप्रभाव देश के 90 फीसदी गरीब लोगों पर पड़ता है और देश के जो 90 फीसदी गरीब लोग हैं, उनमें अधिकांश आबादी ऐसे वर्गों की है, जिनको हम दलितों या पिछड़ों के नाम से जानते हैं अथवा उन्हें धार्मिक अल्पसंख्यकों के नाम से जाना जाता है या सामान्य जाति के गरीब लोगों के नाम से जाना जाता है। वे 90 फीसदी गरीब लोग आज भी महंगाई के इस तांडव से निजात नहीं पा सके। विनियोग (लेखानुदान) विधेयक में अगर सरकार की तरफ से इस महंगाई को नियंत्रित करने का विचार सकारात्मक रूप में आया होता, तब तो शायद देश के लोग कहीं न कहीं अपने आप में राहत महसूस करते। महोदय, दूसरी बात यह है कि पेट्रोलियम पदार्थों के दामों का देश में लगातार बढ़ते रहना जहां आज किसानों के लिए एक बड़ी समस्या है, वहीं पर यह व्यापारियों और तमाम दूसरे वर्गों के लिए भी बड़ी समस्या बन कर खड़ी हुई है। हमारे देश की सरकार ने पेट्रोलियम पदार्थों के दामों में कमी करने के लिए अगर लेखानुदान विधेयक में कोई कारगर कदम उठाए होते, तो यकीनन महंगाई पर काबू पाने की कोई शुरूआत आज हमारे देश में हो सकती थी।

महोदय, तीसरी बात यह है कि आपने मनरेगा योजना का बड़ा गुणगान किया। हो सकता है कि बहुत सारे लोगों को इसका लाभ मिला हो, लेकिन आज की बहुजन समाज पार्टी की ओर से पहले भी हमारी पार्टी की नेता आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी ने सरकार का ध्यान इस समस्या की तरफ दिलाया था कि मनरेगा की योजना, जो देश की सरकार लेकर आई है, उसका समय आपने केवल सौ दिन रखा। उपसभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार से यह कहना चाहता हूं कि साल में 365 दिन होते हैं और आप सौ दिन की रोजगार गारंटी देते हैं, तो 265 दिन एक गरीब आदमी की दिनचर्या चलाने का माध्यम क्या होगा? क्या सरकार ने कभी इस पर चिंतन किया है? अगर नहीं किया है, तो करने की आवश्यकता है।...**(समय की घंटी)**...

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Okay. Please conclude.

श्री नरेन्द्र कुमार कश्यप : महोदय, 'वन रैंक वन पेंशन' बहुत देर से लायी गयी योजना है। आपने इसमें 500 करोड़ रुपये का प्रावधान किया है। मुझे यह राशि कम लगती है। अगर इस पर 2,500 करोड़ रुपये की योजना बने, तो शायद कुछ लाभ मिल सकता है।

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Okay. Please conclude.

श्री नरेन्द्र कुमार कश्यप : महोदय, मैं दलितों के संबंध में एक बात कह कर अपनी बात समाप्त करूंगा।

[श्री नरेन्द्र कुमार कश्यप]

महोदय, इसी सदन में एक मुद्दा हमारी पार्टी की नेता आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी ने उठाया था। जम्मू और कश्मीर के किश्तवाड़ में बहुजन समाज पार्टी के एक नौजवान की हत्या हुई। सरकार की तरफ से सदन में आश्वासन दिया गया था कि सरकार उसके परिवार को आर्थिक सहायता देने पर विचार करेगी, लेकिन आज तक उस मुद्दे पर सरकार ने कोई निर्णय नही लिया। मैं इस ओर भी सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। ...**(समय की घंटी)**...

महोदय, आपने मुझे बोलने का मौका दिया, इसके लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूं।

MR. DEPUTY CHAIRMAN: You are Finance Minister, even then that point should be noted. The point that a *dalit* was killed in Jammu and Kashmir and no action was taken. Please make a note of that and inform the Home Minister. Now, Shri P. Rajeeve. Your time is only three minutes.

SHRI P. RAJEEVE (Kerala): Mr. Deputy Chairman, Sir, actually, the Interim Budget is a combination of false claims and manipulated statistics. The hon. Minister estimates 4.8 per cent growth rate. In this, growth rate of agriculture sector is 4.6 per cent. That shows that the economy has stagnated with the manufacturing sector on the decline. Sir, the Government's main claim is that they could reduce the fiscal deficit. How can they reduce the fiscal deficit? To reduce the fiscal deficit, there are two ways. One, you should increase your revenue. Two, you should reduce your expenditure. Then, what is the revenue side? While giving an answer to my colleague, Shri Tapan Kumar Sen, the hon. Minister said that uncollected tax is Rs. 5.1 lakh crores. As per the Budget documents, Rs. 75,000 crores is undisputed tax, which they could not collect. The hon. Minister gave an answer to me in this House, that Rs. 5,73,626 crores is the latest state of revenue foregone for the corporates. In addition to that, the uncollected tax is 5.1 lakh crore rupees. That is more than 10 lakh crore rupees in these two accounts. Then, you could not increase your revenue side. You could manage the fiscal deficit by reducing the expenditure. The Plan outlay, the total Central outlay, is less than Rs. 66,000 crore. I would give a simple example. The Nirbhaya Fund was declared by the Government in the context of the gang rape in Delhi. You had allocated Rs. 1,000 crores for it in the last Budget. But you didn't spend a single pie under Nirbhaya Fund. I would give one other example. In Kerala, for one big fertilizer industry, FACT, you had allocated Rs. 211 crore in the last Budget. But what is the Revised Estimate? It is 0.1 crore. That means, you gave only one lakh rupees, as per the Budget, for FACT. Mr. Deputy Chairman is well aware of that company. It is a big fertilizer company of this country. The

Budget allotment for it was Rs. 211 crores; but the RE was only Rs. 1 lakh. There is cutting in expenditure.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Only Rupees one lakh!

SHRI P. RAJEEVE: Yes, only one lakh; 0.1 crore of rupees. That is the reality. By cutting this expenditure, the Minister now claims that he could reduce the fiscal deficit. This is actually cutting in expenditure.

Sir, the fiscal consolidation was also achieved through a budgetary contraction, which is contrary to the economy. His second claim is about controlling inflation. Because of lack of time, I would not like to go into the details of it.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: You have already taken three minutes.

SHRI P. RAJEEVE: The Minister gave an answer to me. The food and vegetable prices have been increased by 116 percentage point. Inflation and employment contraction are twin things. It is a very important issue.

Now, I come to the problem of workers who are working in various Schemes. The Prime Minister gave an assurance in the Labour Ministers' Conference. But what is the action of the Government? These Scheme-workers, like Anganwadi workers, are not getting minimum wages. They are demanding minimum wages for the last several years. But there is no allocation for that; there is no declaration for the Scheme workers, the Anganwadi workers and ASHA workers. I request the Minister to make some allotment for these poor persons. Sir, now there are several types of workers — contract workers, casual workers and there is now a new type of workers who are working on honorarium. There are no wages, no minimum wages for them. The Government should spend some money for that.

Then the Government reduced the excise duty on automobile. One important item in this, Sir, is rubber. ...*(Time bell rings)...* The Government reduced the excise duty on automobile.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Now conclude, please.

SHRI P. RAJEEVE: Our demand is to increase the import duty on rubber, and, for FACT and refinery, we demand to reduce the import duty on natural gas. Increase the import duty on rubber and reduce the import duty on natural gas for the benefit of agricultural sector and also for the benefit of industrial sector. But the Government is not ready to do that. Sir, this Budget is totally against the interest of the country.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Okay. All right. Now Shri N.K. Singh. Please take only three minutes.

SHRI N.K. SINGH: Right Sir, as you desire.

Mr. Deputy Chairman, Sir, Mark Twain had once said that truth is more powerful than fiction because fiction has the immense possibilities of manoeuverability, but truth isn't.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: But fiction travels fast.

SHRI N.K. SINGH: Exactly. So, the Budget currency travels faster than the truth of the Budget. There is a ring of fiction in this Budget, a great accounting jugglery in which the Finance Minister has indulged. ...*(Interruptions)*... The Chair has accepted that the Budget is an accounting fiction.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: No, no; the Chair has not accepted it. The Chair has not accepted it.

SHRI N.K. SINGH: Sir, the hon. Finance Minister is happily in Sydney, and may I wish him luck in the deliberations of the G-20! But if the report in the Economic Times and the Indian Express today is correct, the questions which Piyush raised and some of the questions which I wish to raise are the questions which the Finance Minister would need to answer even in Sydney in the deliberations of the G-20.

Sir, I have basically — given the shortage of time — six points to make. First and foremost, it is an accounting fiction because expenditure has been suppressed. There is 90,000 crore rupees cut in capital expenditure, huge cut in infrastructure spending, social spending, and excessive credit has been taken on account of revenues because the revenue account is also fudged up. There is a suppression of expenditure on account of subsidy outgo and the assumptions in regard to GDP growth are fictional.

Sir, for the next year, the FM has taken the credit of a GDP growth of nominal terms, of around 13.6 per cent. If this is true and if inflation is coming down, then you are really assuming a GDP growth of around seven per cent, which is really out of the dreams of anyone.

SHRI RAVI SHANKAR PRASAD: Sir, hon. Member, Shri N.K. Singh, is raising certain fundamental questions. I hope, the very esteemed Minister of State for Finance would reply to those queries substantially. We would like to hear it from him. Please go ahead, Sir.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Okay, please proceed.

SHRI N.K. SINGH: Thank you very much.

Sir, I think the GDP assumptions are not valid. The GDP assumptions are not valid and the inflation assumptions are not valid, and therefore, the assumptions in regard to tax buoyancy are not valid. This much for this year's budget and that much for next year's budget.

Sir, my next point is that an interim budget can't do very much, what the Government has failed to do in ten years. You cannot revive the sagging growth sentiment, which is very serious. You cannot revive investment. My great problem is that what the Finance Minister has done is that he has shoved the problems to his successor. He has shoved the problems to a successor Government in terms of managing the macro-economic stability, in terms of reviving growth sentiment.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Don't go for explanation. Go to the next point. It is already time.

SHRI N.K. SINGH: Yes, Sir.

So, I think that he has shoved the main problems to his successor by following a policy which is anti-growth in the ten years of the record.

My last point, Sir, is that he has gone back on his promises. He had made a solemn promise in the Budget that after the Raghuram Rajan Committee Report, there will be a follow-up action. Two meetings were held by the Finance Secretary. When the time for the third meeting came, and because the FM had to give a compliance statement, he has given a statement that he has sent it to the Planning Commission 48 hours ago. Actually, Sir, there is an enormous deception of the people of the North-East. And we feel exceedingly cheated that on account of political considerations, what is legitimately due to the people of the North-East has been denied.

Sir, I would end up by saying good luck to the Finance Minister's successor, who will have to convert the fiction into a reality, to be able to, therefore, restore macro-economic credibility and to restore investor confidence. That requires a strong and stable Government at the Centre, which I believe, the people of India would deliver.

SHRI RAVI SHANKAR PRASAD: Sir, I have a point of order. Hon. N.K. Singh has used the words 'cheating' and 'deception'. I hope, you will not declare that to be unparliamentary too.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: I would have to look into it.

DR. NAJMA A. HEPTULLA: Sir, he has not called anybody a cheater. ...*(Interruptions)*...

SHRI RAVI SHANKAR PRASAD: Sir, it is a political analysis. ...*(Interruptions)*... Don't do it. Don't do it. ...*(Interruptions)*...

SHRI TAPAN KUMAR SEN: Sir, don't be so generous with expunctions. ...*(Interruptions)*...

DR. NAJMA A. HEPTULLA: Sir, it is absolutely right. ...*(Interruptions)*...

SHRI RAVI SHANKAR PRASAD: Yes. That is why I raised this issue.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: I would look into it and go by the rules. ...*(Interruptions)*...

DR. NAJMA A. HEPTULLA: Sir, an action is being called 'cheating' and 'deception', not any person. ...*(Interruptions)*...

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Now, Message by Secretary-General.

MESSAGES FROM LOK SABHA — *Contd.*

(i) The Delhi Appropriation (Vote on Account) Bill, 2014

(ii) The Delhi Appropriation Bill, 2014

SECRETARY-GENERAL: Sir, I have to report to the House the following messages received from the Lok Sabha, signed by the Secretary-General of the Lok Sabha:—

(I)

"In accordance with the provisions of rule 96 of the Rules of Procedure and Conduct of Business in the Lok Sabha, I am directed to enclose the Delhi Appropriation (Vote on Account) Bill, 2014, as passed by Lok Sabha at its sitting held on the 21st February, 2014.

2. The Speaker has certified that this Bill is a Money Bill."

(II)

"In accordance with the provisions of rule 96 of the Rules of Procedure and Conduct of Business in the Lok Sabha, I am directed to enclose the Delhi Appropriation Bill, 2014, as passed by Lok Sabha at its sitting held on the 21st February, 2014.

2. The Speaker has certified that this Bill is a Money Bill."

Sir, I lay a copy each of the Bills on the Table.